बिहार सर्वेक्षण रिपोर्ट - 2018

(बिहार में शासन के मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं एवं सरकार के प्रदर्शन का संक्षिप्त विश्लेषण)

एडीआर द्वारा रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
टी -95, सी. एल. हाउस, द्वितीय तल,
गुलमोहर कॉमर्शिअल काम्प्लेक्स, गौतम नगर,
नई दिल्ली -110049
फ़ोन: +91-011-41654200
फैक्स: +91-11-46094248

प्रस्तावना और कार्यप्रणाली

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और आरए एस्टरिस्क कम्प्यूटिंग एण्ड डाटा सॉल्यूशंस प्रा० लिमिटेड (आरएएसी) ने किसी देश में संभवतः अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सर्वेक्षण किया है | यह अखिल भारतीय सर्वेक्षण 534 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया, जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकी के 2,73,487 मतदाताओं ने भाग लिया | इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य, निम्नलिखित की पहचान करना थे : (i) शासन के विशिष्ट मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताएं, (ii) उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की मतदाताओं द्वारा रेटिंग, और (iii) मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक | यह सर्वेक्षण, लोकसभा 2019 के आम चुनावों से पहले, अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच किया गया |

बिहार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह रिपोर्ट बिहार के मतदाताओं द्वारा नियत किये गए 10 सबसे महत्त्वपूर्ण शासन के मुद्दों (प्रश्नावली में सूचीबद्ध 31 मुद्दों में से) का विश्लेषण मुहैया कराती है | मतदाताओं की इन प्राथमिकताओं को, उन मुद्दों पर उत्तरदाताओं के अनुभव के आधार पर सरकार के प्रदर्शन के सम्बन्ध में, आगे भी जांचा गया है | इस सर्वेक्षण में बिहार के सभी 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 20,000 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया |

धारणा के इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य - मतदाताओं की सरकार से महत्त्वपूर्ण अपेक्षाएं और वे इसके प्रदर्शन का कैसे मूल्यांकन करते हैं - इसकी बेहतर समझ प्रदान करना है | इसके अतिरिक्त, यह समकालीन समय में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान और शासन पर कार्य के महत्त्वपूर्ण अंतर को भरने का प्रयास करता है | काफी लम्बे समय से, हम पूरी तरह से विभिन्न विशेषज्ञों की राय या विचारधारा पर निर्भर रहे हैं | हालाँकि वह आवश्यक है, हमें मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है | ये प्राथमिकताएं और आकलन समय के साथ बदलते रहेंगे, इसलिए इस सर्वेक्षण को समय-समय पर दोहराने की आवश्यकता है |

अनुसंधान की रूपरेखा: जनसंख्या के विभिन्न खण्डों जैसे ग्रामीण-शहरी, लिंग, जाति, धर्म और आय समूह का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक आंशिक उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन प्रक्रिया का प्रयोग करके 18 वर्ष से अधिक की आबादी के एक व्यापक प्रतिनिधित्व वाले नमूने का चयन किया गया | नमूनों को निष्पक्ष और जनसंख्या का पूरा प्रतिनिधित्व होने का पूरा ध्यान रखा गया | सर्वेक्षण की सटीकता 95% है, अर्थात सही मान सर्वेक्षण के अनुमान के 5% के भीतर हैं |

मुख्य निष्कर्ष

- बिहार सर्वेक्षण 2018 यह प्रदर्शित करता है कि समस्त बिहार में मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं रोज़गार के बेहतर अवसर (49.95%), कृषि के लिए जल की उपलब्धता (41.43%) और बेहतर अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (39.09%) हैं |

- सरकार के प्रदर्शन को, मतदाताओं की सभी तीन शीर्ष प्राथमिकताओं रोज़गार के बेहतर अवसर (5 के पैमाने पर 2.05), कृषि के लिए जल की उपलब्धता (2.08) और बेहतर अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (2.10) पर, औसत से कम रेटिंग मिली |

- ग्रामीण बिहार में मतदाताओं की तीन शीर्ष प्राथमिकताएं रोज़गार के बेहतर अवसर (50%), कृषि के लिए जल की उपलब्धता (48%) और कृषि ऋण की उपलब्धता (42%) हैं |

- सरकार के प्रदर्शन को, ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं रोज़गार के बेहतर अवसर (5 के पैमाने पर 2..06), कृषि के लिए जल की उपलब्धता (2.08) और कृषि ऋण की उपलब्धता (1.91) पर, औसत से कम रेटिंग मिली |

- इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि के लिए बिजली (5 के पैमाने पर 1.93) और कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्यों की प्राप्ति (1.99) पर खराब प्रदर्शन किया है |

- बिहार में शहरी मतदाताओं के लिए तीन शीर्ष प्राथमिकताएं रोज़गार के बेहतर अवसर (47%), पेयजल (46%) और बेहतर अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (43%) हैं |

- सरकार के प्रदर्शन को, शहरी मतदाताओं की शीर्ष प्राथमिकताओं रोज़गार के बेहतर अवसर (5 के पैमाने पर 1.97), पेयजल (2.12) और बेहतर अस्पताल/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (1.97) पर औसत से कम रेटिंग मिली |

- इसके अतिरिक्त, सरकार ने यातायात संकुलन (5 के पैमाने पर 1.91) और घरेलू इस्तेमाल के लिए बिजली (1.98) पर खराब प्रदर्शन किया है |

I. बिहार में मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं और सरकार का प्रदर्शन - समस्त और ग्रामीण एवं शहरी

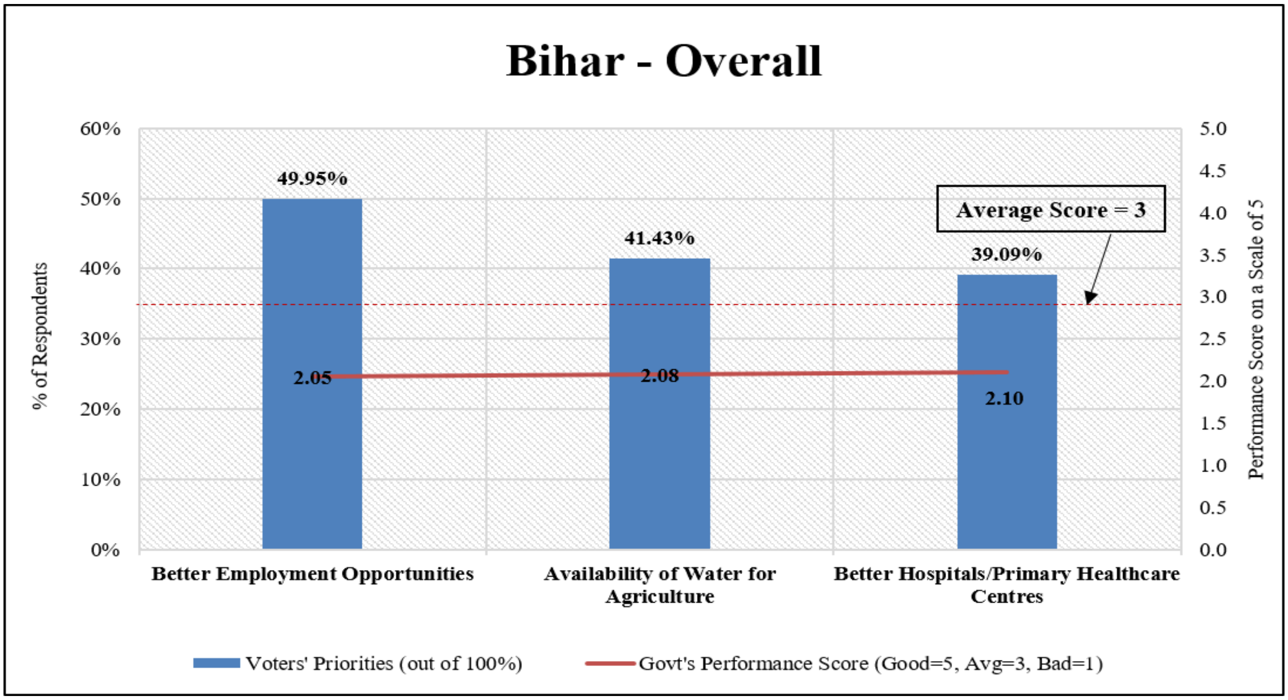

ग्राफ 1: बिहार - समस्त मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं और सरकार के प्रदर्शन की रैंकिंग

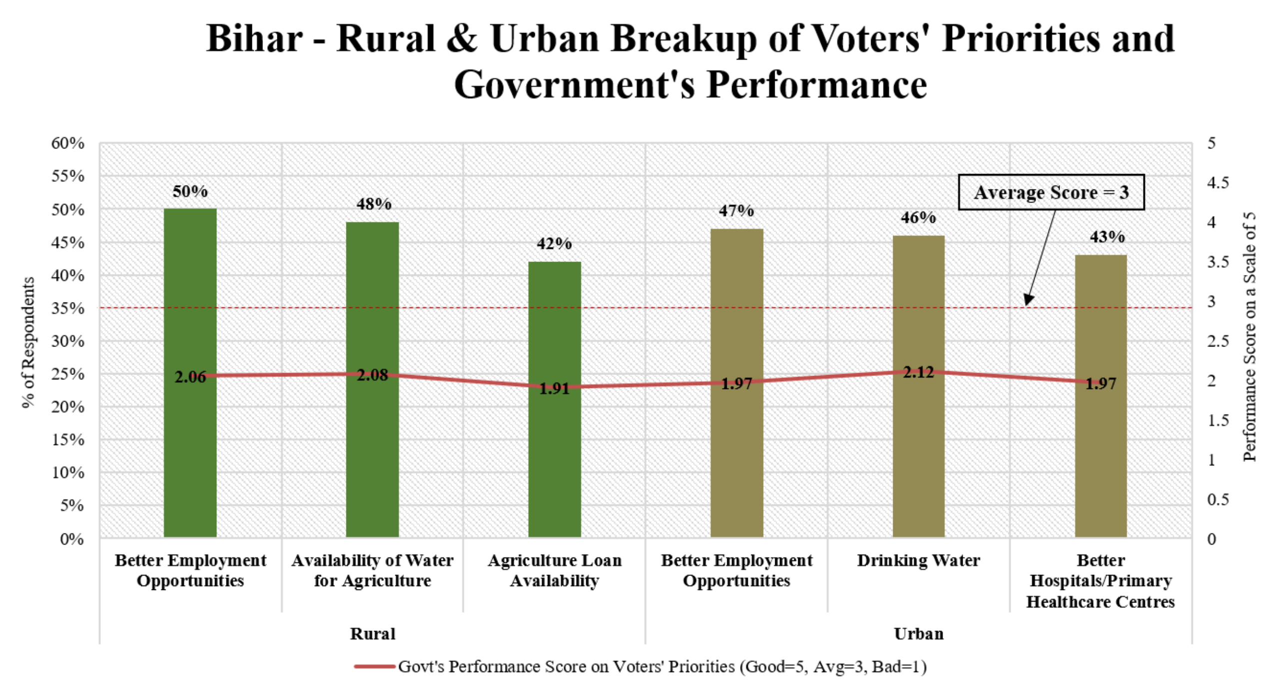

ग्राफ 2: बिहार - ग्रामीण एवं शहरी मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं और सरकार का प्रदर्शन

II. बिहार में ग्रामीण मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं और सरकार का प्रदर्शन

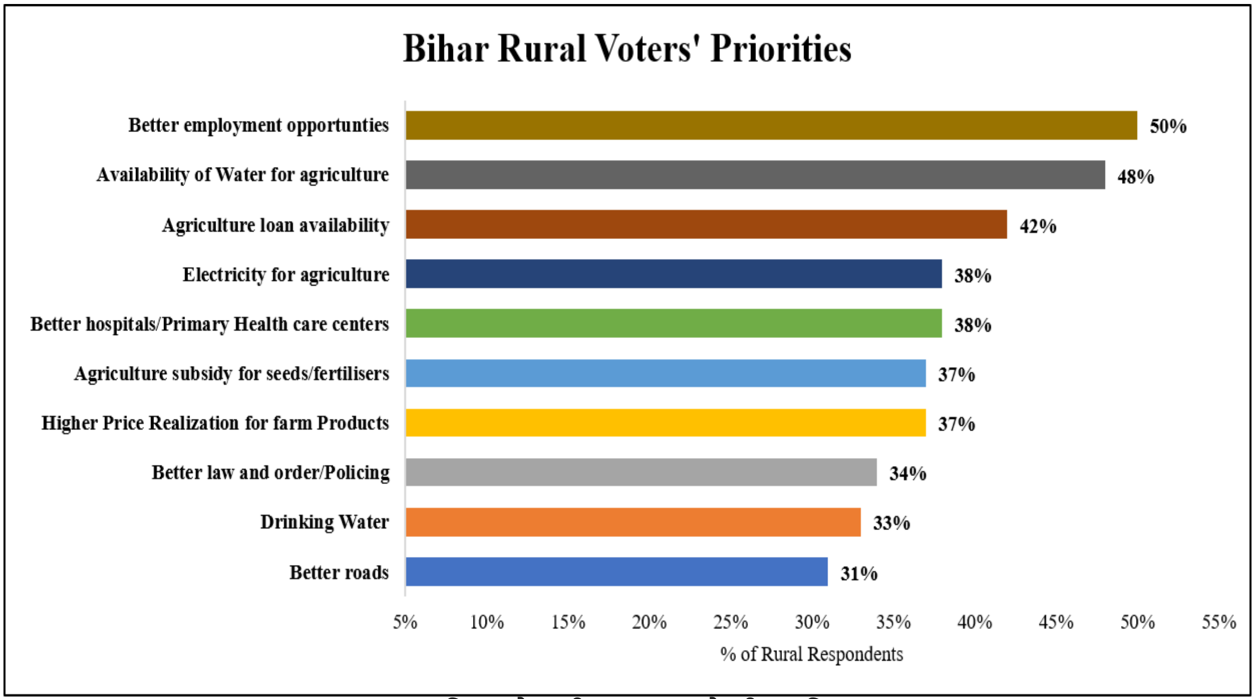

ग्राफ 3: बिहार में ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताएं

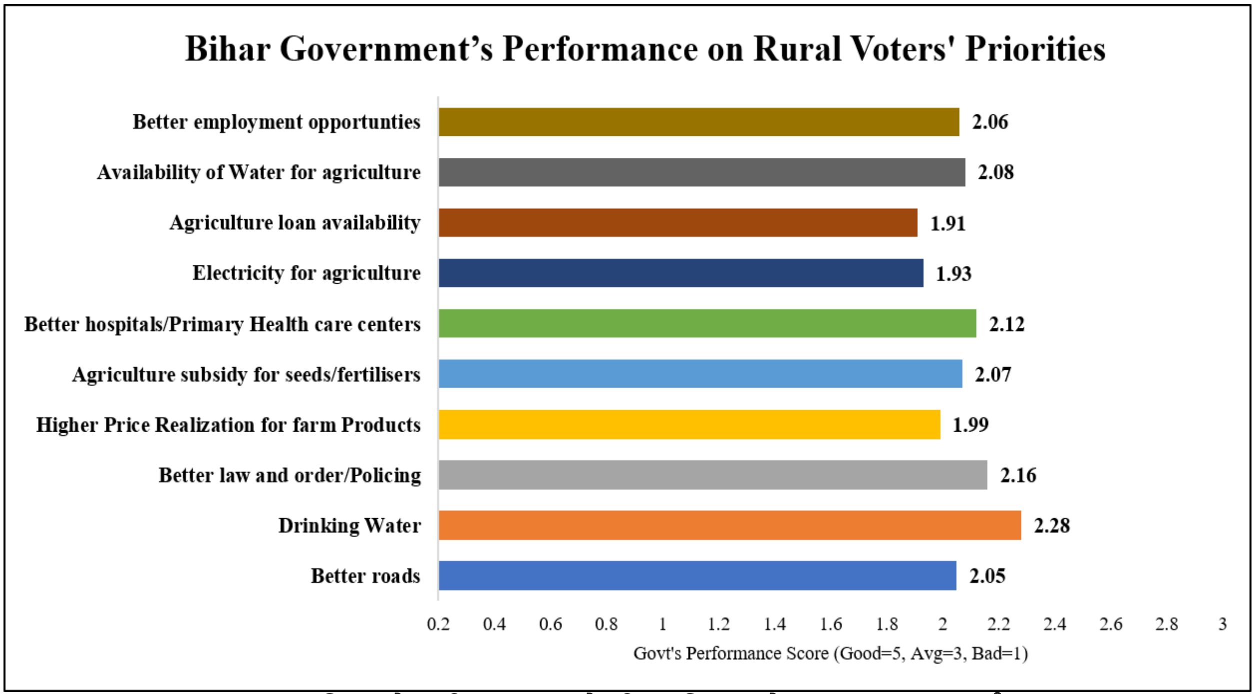

ग्राफ 4: बिहार में ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार का प्रदर्शन

III. बिहार में शहरी मतदाताओं की शीर्ष तीन प्राथमिकताएं और सरकार का प्रदर्शन

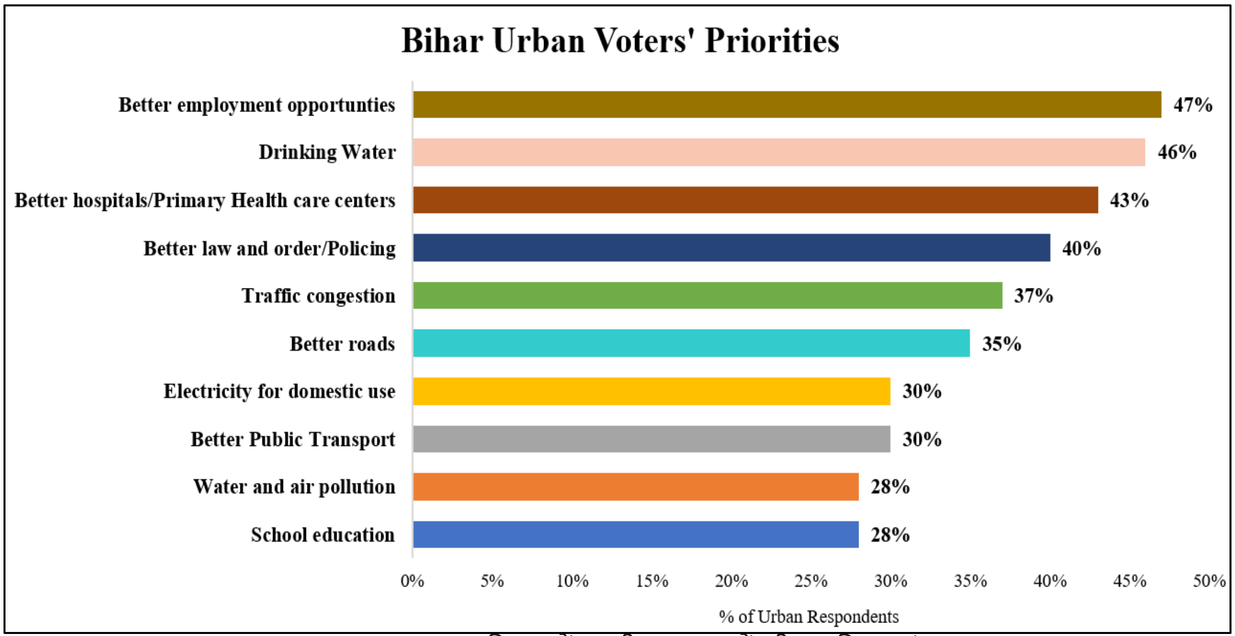

ग्राफ 5: बिहार में शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं

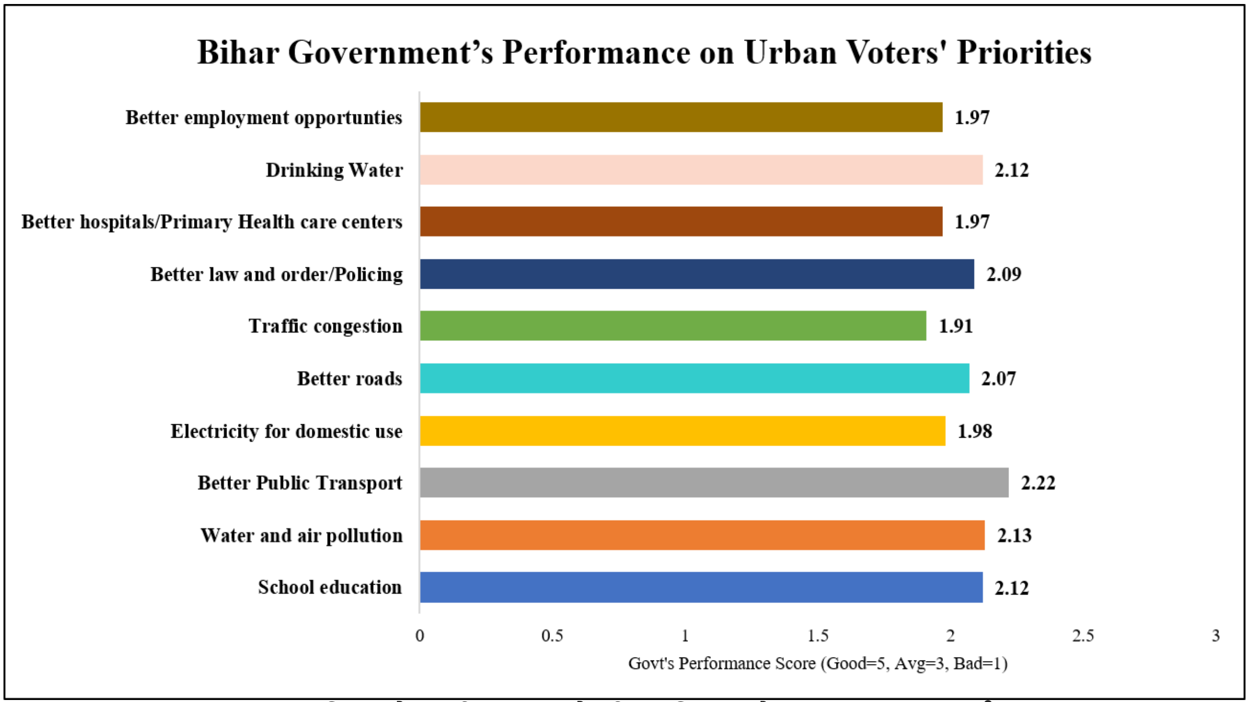

ग्राफ 6: बिहार में शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार का प्रदर्शन

मतदान का व्यवहार

इस सर्वेक्षण ने मतदान व्यवहार के निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया - (i) मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, (ii) आपराधिक प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के बारे में राय, और (iii) अपराध और धन की भूमिका के बारे में मतदाता जागरुकता |

मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित सवाल पूछे गए - "किसी प्रत्याशी को आप किस कारण से वोट देते हैं ?" और "किसी चुनाव में किस प्रत्याशी को वोट देना है, यह निर्णय करते समय किसकी राय अधिक मायने रखती है ?" |

आपराधिक प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के बारे में मतदाताओं की राय को समझने के लिए, जो दो प्रश्न पूछे गए, वह थे - "क्या संसद या राज्य की विधानसभा में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर कोई आपराधिक मामला हो ?" और "लोग आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को क्यों वोट देते हैं?" |

अपराध और धन की भूमिका के बारे में मतदाता जागरुकता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए - "क्या आप जानते हैं कि नकद/धन/उपहार इत्यादि का वितरण अवैध है?", "क्या आपको पिछले चुनाव के दौरान आपके निर्वाचन क्षेत्र में नकद/धन/उपहार/शराब के वितरण की घटनाओं की जानकारी है?" और "क्या आप जानते हैं कि आप प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ?" |

बिहार में मतदान के व्यवहार पर प्रमुख अवलोकन

- बिहार सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, सबसे अधिक मतदाताओं ने कहा कि किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी को वोट करने के लिए मुख्यमंत्री प्रत्याशी सबसे महत्त्वपूर्ण कारण है (महत्त्वपूर्ण:39% और अति महत्त्वपूर्ण 44%) | इसके बाद प्रत्याशी की पार्टी (महत्त्वपूर्ण:54% और अति महत्त्वपूर्ण 27%) और प्रत्याशी स्वयं (महत्त्वपूर्ण:59% और अति महत्त्वपूर्ण 21%) अन्य कारण थे |

- 10% मतदाताओं के लिए (महत्त्वपूर्ण:7% और अति महत्त्वपूर्ण 3%) नकद, शराब, उपहार इत्यादि का वितरण चुनाव में किसी विशेष प्रत्याशी को वोट देने में एक महत्त्वपूर्ण कारक था |

- यह निर्णय करते समय कि चुनाव में किस प्रत्याशी को वोट देना है, बिहार के 86% मतदाताओं ने बताया कि उनकी स्वयं की राय सबसे अधिक मायने रखती है | 6% मतदाताओं के लिए उनके पति या पत्नी और 5% मतदाताओं के लिए उनके परिवार के सदस्यों की राय अधिक मायने रखती है |

- मतदाताओं की एक बड़ी संख्या (72%) को पता था कि नकद/उपहार इत्यादि का वितरण अवैध है |

- 16% मतदाताओं के कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं की जानकारी है जहाँ मतदाताओं को उनके वोट के बदले में इन प्रलोभनों की पेशकश की गयी थी |

- 98% मतदाताओं का मत था कि संसद या राज्य की विधानसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी नहीं होने चाहिए |

- केवल 22% मतदाता जानते थे कि वह प्रत्याशियों के आपराधिक रिकार्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

- 37% मतदाताओं को यह लगता है कि लोग ऐसे प्रत्याशियों को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होती |

- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को वोट करने के सम्बन्ध में 35% मतदाताओं को यह लगता है कि लोग ऐसे प्रत्याशियों को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि प्रत्याशी अन्यथा अच्छा काम करता है |

- जातिगत और धर्म पर आधारित सोच भी 35% मतदाताओं के लिए आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले प्रत्याशियों को चुनने में महत्त्वपूर्ण कारक है |

- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को वोट करने में अन्य महत्त्वपूर्ण कारक यह भी है कि इन प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर प्रकृति के मामले नहीं हैं (35%), प्रत्याशी शक्तिशाली है (35%) और प्रत्याशी ने चुनावों में बहुत अधिक धन खर्च किया है (35%) |

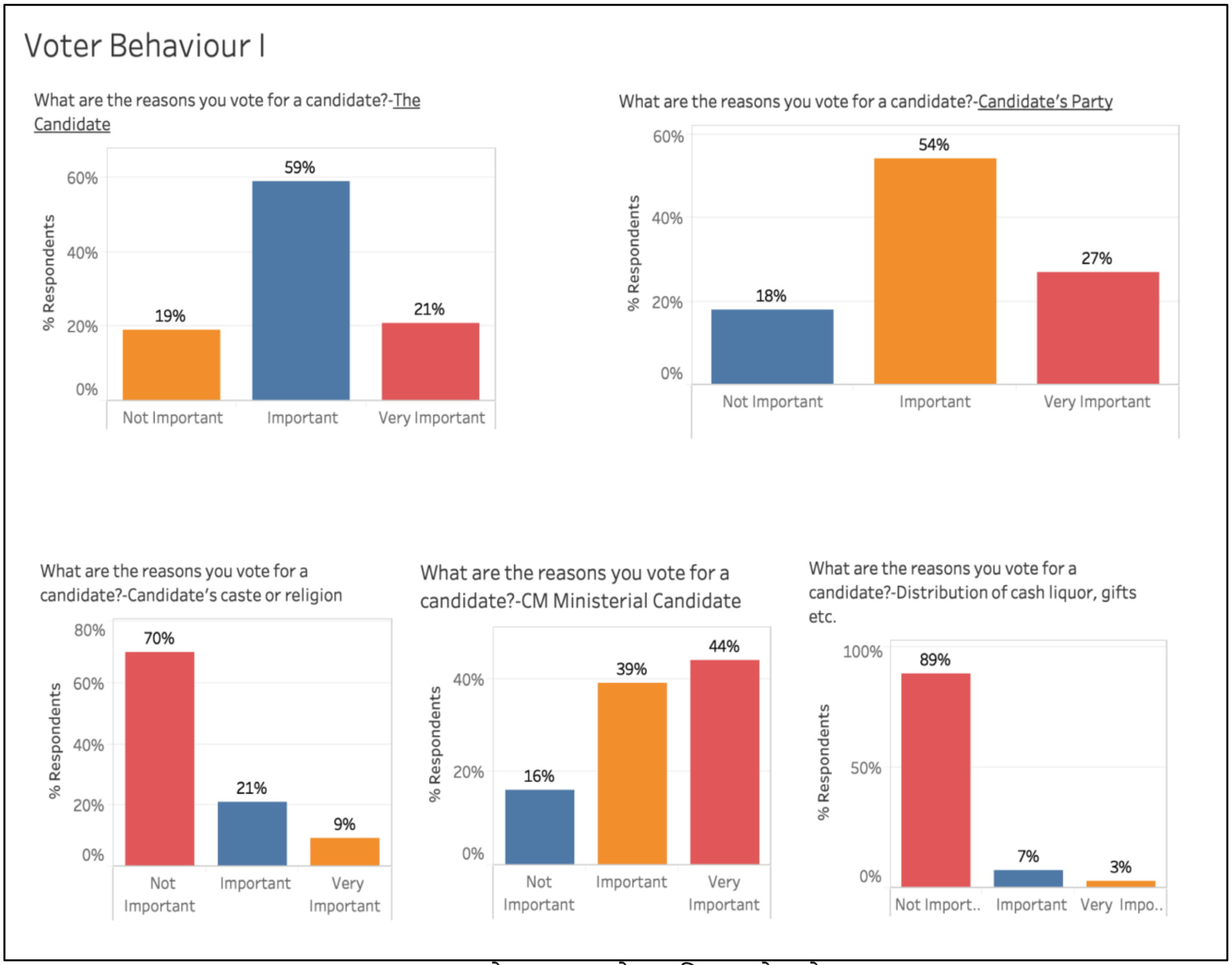

ग्राफ 7: मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

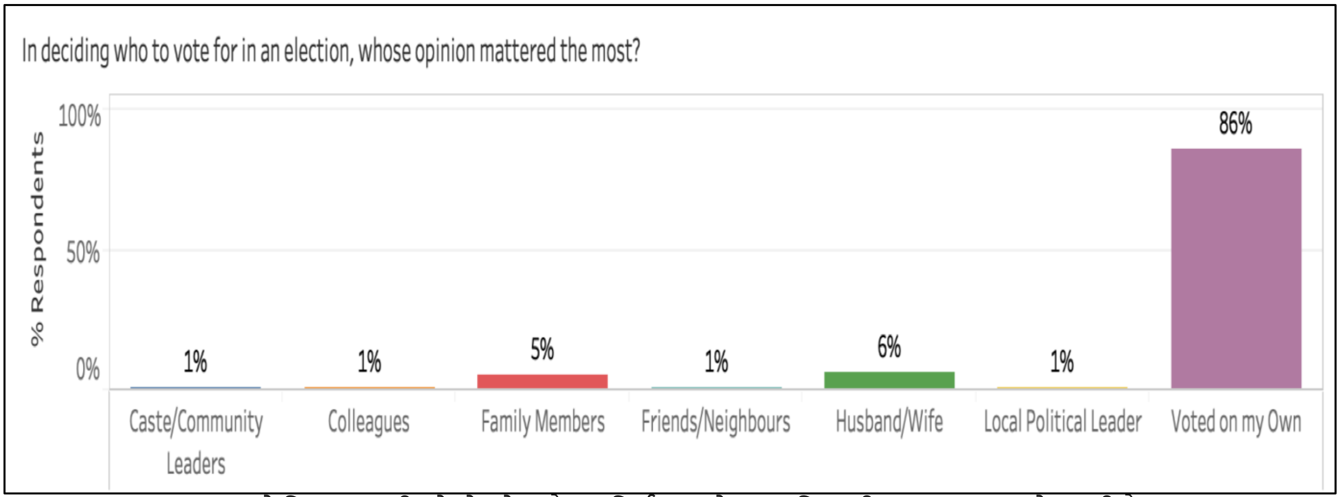

ग्राफ 8: चुनाव में किस प्रत्याशी को वोट देना है यह निर्णय करते समय किसकी राय ज्यादा मायने रखती है

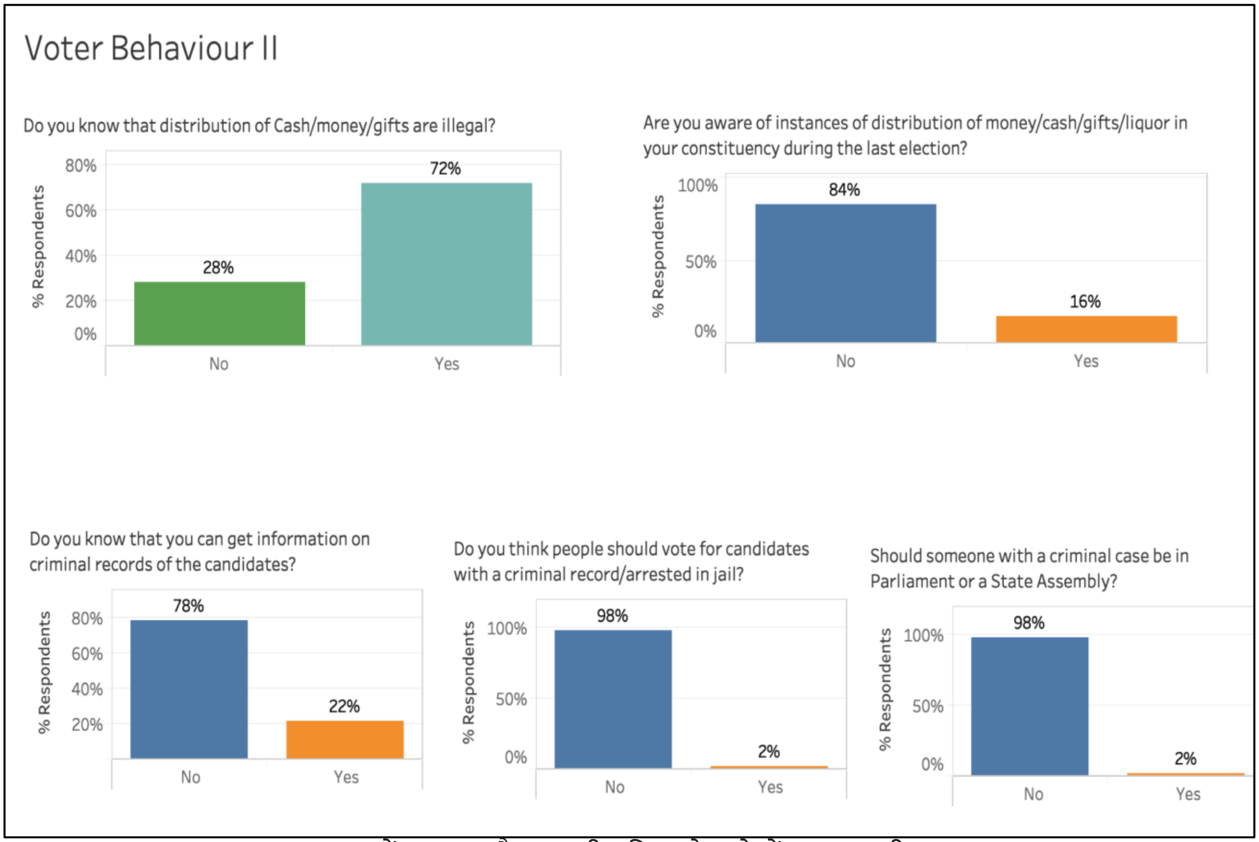

ग्राफ 9: चुनाव में अपराध और धन की भूमिका के बारे में मतदाता की जागरुकता

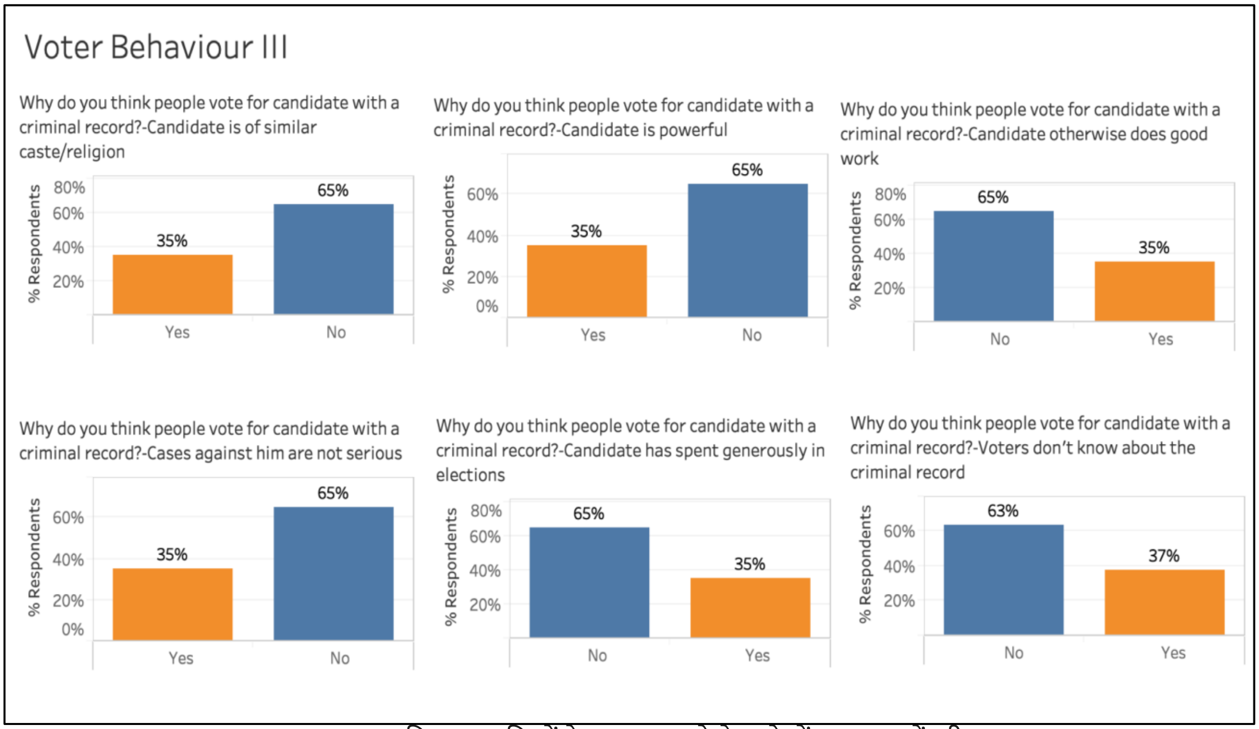

ग्राफ 10: आपराधिक प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के बारे में मतदाताओं की राय

मतदाताओं का जनसांख्यिकीय विवरण

- सर्वेक्षण किये गए मतदाताओं में से 87% ग्रामीण क्षेत्रों से और 13% शहरी क्षेत्रों से थे|
- 64% पुरुष थे और 36% महिलाएं थीं|
- 67% सामान्य जाति से, 17% ओबीसी से, 15% एससी से और 1% एसटी से थे|

उत्तरदाताओं के अन्य विवरणों को नीचे दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है|

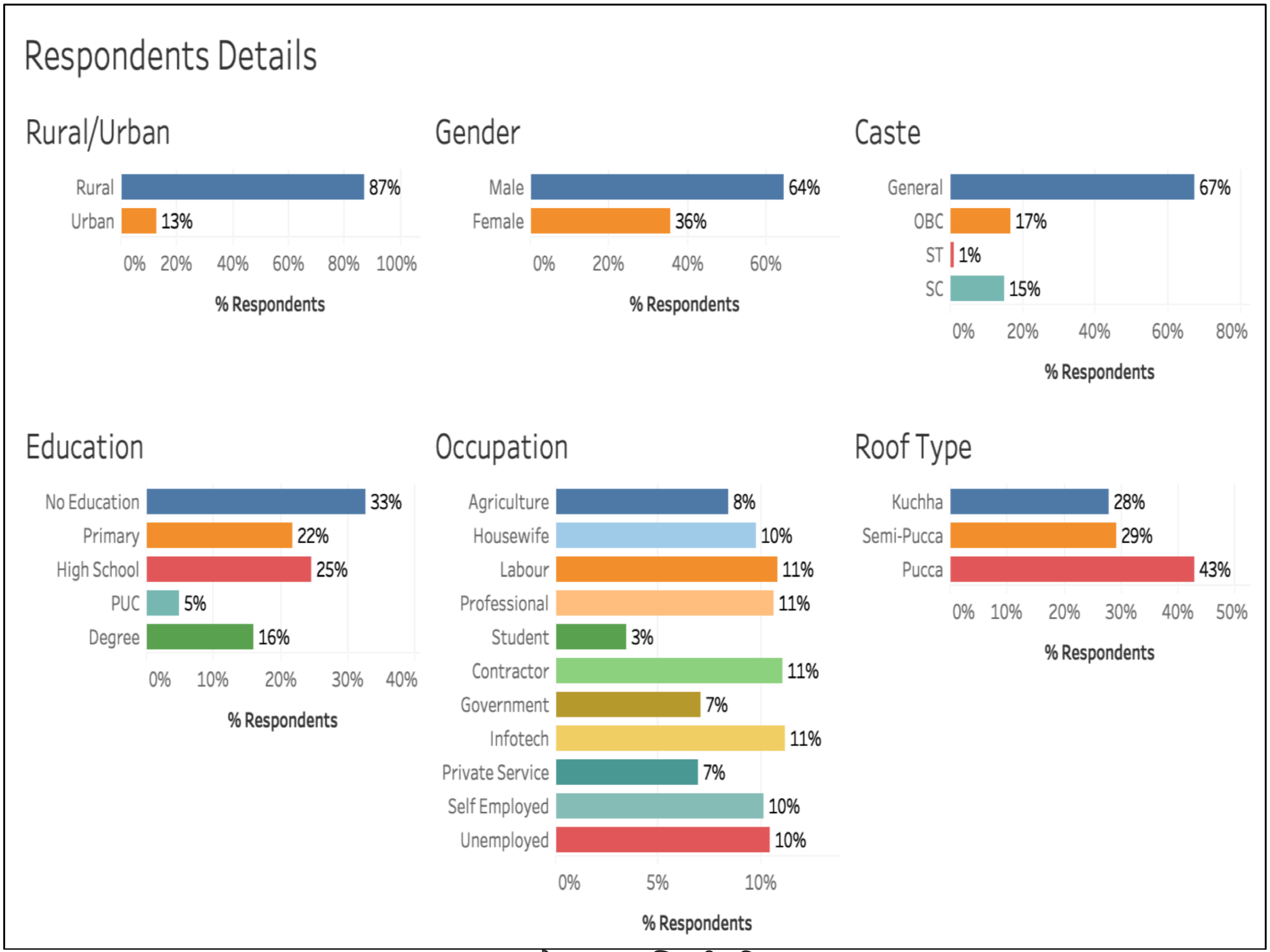

ग्राफ 11: मतदाताओं का जनसांख्यिकीय विवरण

निष्कर्ष

बिहार सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि बिहार में सरकार द्वारा मतदाताओं की प्राथमिकताओं की उपेक्षा की गयी है | यह इस तथ्य से पूर्णतया स्पष्ट है कि सरकार ने शासन के सभी सूचीबद्ध मुद्दों पर ख़राब एवं कमतर प्रदर्शन किया है | बिहार में मतदाताओं की प्राथमिकताओं और सरकार के प्रदर्शन की प्रवृत्ति का विश्लेषण सरकार और क़ानून-निर्माताओं के समक्ष कुछ विकट प्रश्न खड़े करता है -

- क्या बुनियादी ढांचा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीतियों के सम्बन्ध में लिए जाने वाले निर्णय सर्वसमावेशी सामाजिक कल्याण के बदले में समाज के कुछ वर्गों के पक्ष में लिए जाते हैं?
- क्या सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह मतदाताओं की प्राथमिकताओं के अनुसार बजट व्यय को पुनः निर्दिष्ट करे / योजना बनाये?
- राजनीतिक दलों को घोषणा-पत्र में किए गए वादों को निभाने में अधिक जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है?
- समाज के वंचित वर्गों को रोज़गार, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नीतियों में क्या बदलाव किये जाने की आवश्यकता है ?

यह तथ्य कि एक बार राजनेता के चुन लिए जाने के बाद मतदाताओं की कोई भूमिका नहीं रह जाती है, निर्वाचित प्रत्याशी की प्राथमिकता को राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित किये जाने की अनुमति देता है | अतः ऐसी आशा की जाती है कि मतदाता अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतर राजनेता को चुनने में सावधानी बरतेंगे | राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ राजनीति और शासन में मतदाताओं की पसंद को शामिल करना है |

इन मूल्यांकनों के पीछे वह सच्चाई है जिसका हमारे देश में रहने वाले लोग हर दिन सामना करते हैं | ये मूल्यांकन इसी सच्चाई को दर्शाता है और हमारी सरकार को यह बताने में मदद करता है कि इन संख्याओं का क्या अर्थ है और इस देश के मतदाता सरकार को कैसे देखते हैं |

अस्वीकरण

इस सर्वेक्षण को शासन के उन सबसे अधिक ज्वलंत मुद्दों का पता लगाने के लिए किया गया था जिन्हें भारत के मतदाता अपने दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हुए पाते हैं और यह भी जांच करने के लिए कि मतदाता उन मुद्दों के समाधान के लिए अपनी सम्बंधित सरकार से खुश हैं या नहीं |

इस सर्वेक्षण को स्वस्थ वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा किया गया और मान्यता प्राप्त डाटा विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करके परिणामी निष्कर्ष और रिपोर्ट्स को तैयार किया गया | इस रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्ष भारतीय मतदाताओं द्वारा दी गयी प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं |

यह सर्वेक्षण भारत के मतदाताओं की शासन की मांग और भारतीय मतदाताओं की नज़र में सम्बंधित सरकारों द्वारा इसकी पूर्ति के बीच के अंतर के अध्ययन का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास है | यह सर्वेक्षण किसी भी तरह से किसी सरकार या राजनीतिक दल या व्यक्ति या किसी अन्य संगठन या संस्था की प्रशंसा करने या निंदा करने का प्रयास नहीं है |

इस रिपोर्ट में निहित डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एडीआर द्वारा हर संभव प्रयास किये गए हैं |

इस रिपोर्ट का प्रयोग करने वाले या इससे उद्धरण करने वाले किसी भी व्यक्ति को 'बिहार सर्वेक्षण रिपोर्ट - 2018' को स्रोत के रूप में स्वीकार करना चाहिए |

ADR Association for Democratic Reforms

To Get Information About Candidates/Parties/MPs/MLAs/ Corporators/PILs in courts

myneta.info National Election Watch

Give us missed call on: **08010445555**

Toll Free Helpline No: **1800-110-440**

Journalist Helpline no: **8010394248**

Subscribe to ADR on **WhatsApp** for updates: **7840067840**

Visit: **www.myneta.info**

Email: **adr@adrindia.org**

Send SMS: **Myneta <pincode or constituency> to 56070 or 9212356070**

To contact ADR State Partners, visit: **https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators**

Social Media

/myneta.info /adrindia.org @adrspeaks /adrspeaks /adrspeaks

https://in.linkedin.com/company/association-of-democratic-reforms-adr-

Our Websites

www.adrindia.org

Provides detailed analytical reports of Lok Sabha, State Assemblies, local body elections & financial reports of political parties & ongoing PILs in courts

www.myneta.info

Provides full information of criminal cases, asset, liability and education details declared by candidates in the self sworn affidavits

Android Apps

Myneta: The criminal, financial, educational & other background information self declared by candidates in their affidavits during elections is now available on your mobile phones.

Election Watch Reporter: This app provides a tool to the citizens to capture violations of election related laws & the code of conduct.

Both the applications are available on Google Play Store.